ernment interfered in the judicial process; the Law Minister interfered in the judicial process; the Law Minister discussed with the Chief Justice of India the case which was pending before the Subordinate Court. The Law Minister promoted him and kept his promotion pending saying that the promotion can be had only after the case is disposed of.

This is an atrocious interference in the judicial process. It is absolutely inconceivable. Therefore, the judgment becomes suspect; the judge becomes suspect. That is the product of connivance and conspiratorial arrangement under the carpet, under the temptation in hustling a thing. This is the circumstance under which thi has been done. It is most atrocious of all persons, Mr. Shanti Bhushan should not have done this.

That is all I have got to say. I am sorry that the clean hand of Mr. Shanti Bhushan became soiled as a Minister in the matter of judicial process. I am sorry about it. This is all I have got to say. I do not want to reply to many things, to the vituperative fulminations and the characteristic way Mr. Chatterjee indulged in. He could have the pleasure of doing it. I do not want to reply to that. This is not the time to do that. (*Interruptions*). He has developed a great fascination for the judiciary. I only want to remind him of what the great leader, Shri E. M. Shankaran Namboodripad said, namely that the judges in India are the product of a Bolshevik. He had to stomach it. That was the certificate he had given. (*Interruptions*) I have seen enough of the great performance; I have seen enough of the brand democracy; I have seen enough of his love for democracy; I have seen enough of your love for the country; I have seen enough of your love for the judiciary; I have seen enough for the partiality of the judiciary. That is all I want to say.

MR. CHAIRMAN: Now we have to take the Half-an-Hour Discussion.

SHRI C. M. STEPHEN: I will conclude.

MR. CHAIRMAN: It is 5-30 P.M.

SHRI C. M. STEPHEN: I will just take two to three minutes more You may put it to vote next time. I do not want to delay the Half-an-Hour Discussion. At 5-30 P.M. it nas got to be taken up.

MR. CHAIRMAN: It is already 5-30 now. Now, we take up the Half-an-Hour Discussion.

17.30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Alleged irregularities in Indian Institute of Technology, Kanpur

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, यह आई आई टी, कानपुर के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रकार की अनियमितताये और भ्रष्टाचार के आरोप आए है, उनके सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा है ।

"The crisis of confidence in the IIT Kanpur has reached a point where only a full-fledged inquiry will satisfy the warring factions. The reluctance of the Ministry of Education to institute a probe even when a large number of alleged financial and administrative irregularities—some of them apparently serious—have been brought to the notice of the President, Mr Reddy who is the Visitor of the Institute is not understandable."

सभापति महोदय, इसके पहले कि और बातें मैं रखूं, मैं कहना चाहूंगा कि आई आई टी कानपुर राष्ट्र की कितनी बडी सम्पत्ति है यह इस इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट, 1977-78 से प्रकट होता है कि :

इक्वीपमेन्ट	. .	852 लाख
फर्नीचर	. .	854 लाख
बुक्स वगैरह	. .	164 लाख

[डा० रामजी सिंह]

कहा जाता है कि यह संस्थान काफी बड़ा और उपयोगी है । मैं यहां पर अखबारों की बात नहीं कहना चाहता । मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, डिपार्टमेन्ट आफ सोशल वेलफेयर के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी की 1977–78 की जो रिपोर्ट है उसके कुछ अंश मैं यहां पढ़ना चाहूंगा । बाहर की बातें तो गलत हो सकती हैं लेकिन एस्टीमेट्स कमेटी की बातें गलत नहीं हो सकती हैं । अपेंडिक्स (8) में जो ममरी आफ रेकमेंडेशन्स दी हुई है उसमें से थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा

"IIT Bombay and Kanpur are yet to formulate proposals. The Committee are unhappy over the inordinate delay in the implementation of the recommendation of All India Council for Technical Education."

यह है आई आई टी की स्थिति । आप टेक्निकल एजूकेशन कमेटी की सस्तुति पर भी ध्यान नहीं देते हैं ।

इतना ही नहीं, आप इसकी रेकमेंडेशन 215 को देखें

"The Committee are unhappy to note that there was delay in starting reservation of seats for scheduled cases and scheduled tribes candidates in the Institute while IIT Bombay and Delhi started reserving seats from 1968 this IIT started reservation from 1974 for post-graduates and administration."

वहां के शेड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेन्ट्स ने भी लिख कर भेजा है कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है । इसके अलावा रेकमेंडेशन 282 और 283 को भी आप देखें

"The Committee are distressed to note that there was inordinate delay in submission of the Reports of Reviewing Committee particularly by the Reviewing Committee on IIT, Kanpur."

तो यह है वहां की जन्म कुण्डली । लोगों को लगता होगा कि कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ हमारे सदस्य इन बातों को उठाते हैं लेकिन यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है ·

"The Committee desires that an indepth study may be undertaken to assess the extent of utilisation of the costly sophisticated equipment available in the I.I.T. with a view to taking necessary measures for their fuller utilisation."

मैं एक दो उदाहरण और रखना चाहूंगा । 563 में वह कमेटी कहती है .

In the case of IIT, Kanpur, the recommendation has not been implemented at all on the plea that there is shortage of accommodation and difficulties in schooling for children.

The Committee are disappointed to find the progress made in implementing the Faculty Exchange Programme amongst IITs. and Indian Institute of Science in pursuance of the Visitor's orders issued in Sepember, 1974 is very slow.

इस में सब से ज्यादा जो सेंसर किया गया है, वह आई० आई० टी० कानपुर को किया गया है । इतना ही नहीं, एस्टीमेट्स कमेटी की केवल एक बात रख कर मैं इस को समाप्त करूंगा क्योंकि वह बात बहुत इम्पोर्टेंट है । उस ने कहा है 623 में

The Committee are concerned to note that while IIT Madras and IIT Bombay earned Rs. 12.94 lakhs and Rs 11.21 lakhs respectively during 1976-77, the IIT Kanpur earned only Rs. 4.31 lakhs.

यह है जो एस्टीमेट्स कमेटी ने कानपुर के बारे में कहा है । मेरे पास तो आरोपों का बन्डल है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं रखना चाहूंगा, जिस का मैं प्रमाण न दे सकूं । सब से पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि :

The sale of computers IBM 7044 and 1401 at a loss of lakhs.

अब यह टेन्डर जो दिया गया है, इस टेन्डर में इस्टीट्यूट को लास हुआ है । पचास लाख रुपये का टेंडर आया था लेकिन एक्सेप्ट किया कम का । मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगा । यह रिकार्ड मेरे पास है । इस में एन० सदासीवन ने आई०बी०एम० 1401 के लिए 20 लाख रुपये और इन्डियन डेटा प्रोसेसर्स ने 30 लाख रुपये का टेन्डर दिया था लेकिन टेन्डर 20 लाख का एक्सेप्ट किया गया । आई०बी०एम० 7044 के लिए सदासीवन ने 20 लाख रुपये का टेन्डर दिया था और इन्डियन डेटा प्रोसेसर्स ने 15 लाख रुपये का । इस तरह से 5 लाख रुपये का लास हो गया । यह रुपया कहां चला गया । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की सम्पत्ति से खिलवाड़ किया गया और ये 5 लाख रुपये उनसे वसूल करने चाहिए जो दोषी हैं । मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि और दूसरे वक्ता इस के बारे में कहेंगे ।

इसी तरह से श्री जे० एल० उपाध्याय की बात है। Payment of Rs one lakh to Shri J.L Upadhyay.

ये वहां पर थे और उन के बारे में यह तय हो गया था कि उन को 30 हजार रुपया दे दिया जाए और वे क्रिमनल केस लौटा लेंगे। राष्ट्र की सम्पत्ति के साथ खिलवाड करने वाले बदमाशों ने क्या किया कि 30 हजार के बदले एक लाख रुपये देने पड़े ताकि वे अपना क्रिमनल केस वापस ले लें। इस तरह से ये जो 70 हजार रुपये हैं, ये उन से वसूलने चाहिए, यह मेरा दूसरा चार्ज है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जरनल्स के लिए जो एडवान्स दिये गये, उन का एडजस्ट नहीं किया गया।

Advances made for journals not adjusted:—Advances upto Rs 10 to 15 lakhs towards subscription to journals are made every year to M/s. Allied Publishers No effort by the Accounts Section is made to get the report about the receipt of the journals ordered. The advances given to the Allied Publishers are shown as expenditure without adjusting the same.

न भूल लिख्यते किंचित्। यह उन के बारे में है।

इसी तरह से मैं एक लेटर और पढ़ देना चाहता हूं कि किस तरह से सेन्ट पर सेन्ट एडवान्स एलाइड पब्लिकेशन प्राइवेट लि० को दिया है। यह जनवरी 8, 1979 का डी० ओ० लेटर है।

This is to refer to your D.O letter No Dated 6th January, 1979 which has been delivered to my office on 8th January, 1979, regarding cent per cent advance payment made to M/s. Allied Publication Private Ltd., New Delhi, amounting to Rs. 6.51,648.

यह मेरा लिखा हुआ नहीं है। इस में यह और लिखा हुआ है :

Accounts Section does not get any Report from the Library in regard to these advance payments. The *status quo* regarding this could be checked from the Library, if you so desire.

अब चौथी बात मुझे आप से कहनी है - the use of aircraft for private visit

यह मैं इस में नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी का 5652 क्वेश्चन है और इस का उत्तर दिया है। इस में कहते हैं कि भोपाल गये, इन्दौर गये। वहां सजय गांधी का और इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिये गये। पूछने पर कहते हैं कि अपने खर्चे पर गये, पैट्रोल का खर्चा किया। यह भी कहते हैं कि हवाई जहाज हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। उनको हम मेन्टेन करते हैं इस को हम मेन्टेन करते हैं इस तरह से कहना सरासर गलत है।

पांचवीं बात मैं आप के सामने रखना चाहता हूं— Adjustment of Rs. 15,000/- against Imprest Rs. 2,000.

The Director ordered the adjustment of an amount of Rs. 15,000/- spent by the Department of Chemical Engineering as against a permanent sanctioned imprest of Rs. 2,000/- particularly when the vouchers submitted by the Department were found mutilated and erased. The objections were over-ruled.

जैसे इंदिराजी के राज्य में अपनी मर्जी से होता था वैसा ही अब भी होता है। मेरे पास यह फोटो स्टेट कापी है। इतने कम समय में सब तो नहीं पढ़ी जा सकती है केवल थोड़ी सी आप को पढ कर सुनाता हूं—

"Since the matter has come to the notice of the authorities and a Committee has been appointed by the Director to examine the vouchers, the procedure for adjustment of remaining vouchers can now be initiated only, on the basis of the statement recorded by the Committee for further recommendation"

सभापति महोदय, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। अब दूसरी बात यह है—

"Advance made to non-existing firms"

इन को पकड कर के जेल में रखने की बात है। कोई फर्म नहीं है, उसे एडवांस दे दिया है। जिस ने इस को दिया उसे जेल में रखना चाहिए।

"An order was placed by Purchase Section vide purchase order No. P 6 E. 29/73-74/600 dated 25-9-73. The Institute made 90 per cent advance to the firm through bank which was in excess by Rs. 60.26 "

जब यह एक्सेस मिला तो पता लगा कि किसी नान एग्जिस्टिंग फर्म को यह दिया गया और एक्सेस एमाउन्ट दिया गया। बाद में पता चला कि लापता, बेनामी फर्म को दिया गया। यह बात मैं बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूं। यह सुपरिन्टेन्डेन्ट का लिखा हुआ है। ये सब कागज पत्र हम शिक्षा मंत्री जी को दे देंगे। हमें उन पर विश्वास है कि वे न्याय करेंगे।

[डा० रामसिंह]

"Against our P.O. No. 50 and 50 dated 25th September 1963 placed with M/s. N J Electronics, Bombay, an advance of Rs 825 20 was paid to the firm being 90 per cent against document through Bank '

यह जो सारा हुआ है इस का कोई पता नहीं, इस फर्म का कोई पता नहीं है ।

इन सारी चीजों में इर्रेगुलरिटी हुई है । समय की सीमा के अन्दर मैं एक चीज कहना चाहता हूं — Misuse of the statutory provision

हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं तो हम को चुप हो जाना पड़ता है । हम आप को रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाते हैं—

'The Institute is an autonomous organisation incorporated under the Act of Parliament 1961 and is wholly financed by the Central Government It is functioning under the Ministry of Education, Government of India The formations of various constituent bodies such as I I T Councils Board of Governors of various constituents Building and Works Committee, Finance Committee, Senate, etc constitute under the Act and the Statutes which govern and guide the institute functioning in the areas of administration, academic including curricula and syllabi, construction and repairs of major and minor works, Budget, etc "

उनको यह भी पढ़ना होगा । यह मिसयूज आफ स्टेचुटरी प्राविजन है । यह धोखा देने वाला है । यह स्टेचुटरी प्राविजन नहीं हो सकता है ।

"A gross misuse of the statutory provisions to favour individuals is exemplified in the appointment of Dr. N C Nigam as Deputy Director In violation of the past practice of constituting a regular selection committees, the Chairman BOG exercised his 'discretion' to constitute an *ad hoc* Selection Committee and rushed through the appointment of Dr. N. C Nigam as Deputy Director."

मैं इतना ही कहूंगा कि डायरेक्टर ने अपने मन से स्टेटिस्टिक्स लिये हैं ।

इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि वायोलेशन क्या है किसी एप्वाइंटमेंट में । लेकिन केवल एक आदमी ही इंटरव्यू में आये थे और स्टेचूट को धागा को तोड़ मरोड़ कर के एक आदमी को बहाल कर लिया था। अब स्वायत्तता क्या करेगी, कैसे शिक्षा मंत्री हस्तक्षेप करेंगे ?

मैं जानता हूं कि आई आई टी कानपुर में रिसर्च किस प्रकार से होता है क्योंकि मैं ने वहां पी एच डी के लिए रिसर्च किया है । रिसर्च कैसे होता है मैं जानता हूं । डबल डाक्ट्रेट यह है । आधे दर्जन लोगों ने रिसर्च किया था । यहां पर एक सज्जन मनोहर प्रसाद जी—मनोहर लाल नहीं, मनोहर प्रसाद—उन्हों ने रिसर्च का थीसिस जमा किया । चार एग्जैमिनर होते हैं । अब स्टेचट कहता है कि अगर तीन एप्रूव कर दें और रिपोर्ट कर दें तो उस को पी एच डी मिल जानी चाहिये । तीन ने रिपोर्ट कर दी, एक ने डिफर किया रहा । अब तीन के रिपोर्ट करने के बाद भी उस को नहीं दी गई । मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी ने जिस ने नहीं दी अगर कोई पी एच डी की डिग्री उस के पास है तो वह उस से छीन ली जानी चाहिये । जो इस तरह से रिसर्च की महत्ता के साथ खिलवाड़ करता है उस के पास यह डिग्री नहीं रहनी चाहिये ।

मैं शिक्षा मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । और न ही उन के बारे में पक्षपात की बात मैं कह रहा हूं । उन की न्यायप्रियता में हम विश्वास है । सारी चीज की जांच हो रही है यह मंत्री महोदय कहेंगे । लेकिन वह मौखिक रूप से हो रही है । वह हो भी चुकी होगी । लेकिन जो प्रमाण मैं ने दिये हैं मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के पांच सदस्यों की जिस में जनता के पक्ष भी और विरोधी दल के भी सदस्य हों और शिक्षक भी हों जो एक से एक बढ़ कर हैं और लायक भी हों, आप समिति बनायेंगे जो जांच कर और जांच कर के अगर वह कुछ लोगों को दोषी पाये तो क्या आप उन को दंडित करने के लिये तैयार हैं । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और ऐसे ही छानबीन करते हैं तो इस का सारा कलंक हमारे ऊपर लगेगा । झाड़ फाड़ वाली बात नहीं होनी चाहिये । जो रूल्ज को तोड़ मरोड़ रहे हैं, न्यायप्रियता और शिक्षा की स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्हों ने राष्ट्र की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है, रिसर्च के कानून को तोड़ कर डिग्री उस को नहीं दी है और इस सब के लिये जो अपराधी है, दोषी है, उन का पता लगाने के लिये क्या आप संसदीय समिति का निर्माण करेंगे और निष्पक्ष जांच इस सब की करवायेंगे ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER): I should, at the outset, thank Dr. Ramji Singh for admitting that the IIT is a very prestigious institution. Not only this IIT Kanpur is there, but

there are 4 other IIsT which are producing the best of the technicians in the country, who are also highly regarded in foreign advanced countries.

He has rightly pointed out that the IIsT should be looked after with sufficient care. He has referred to the Report of the Estimates Committee. Whenever there is any Report of the Estimates Committee or of the Public Accounts Committee, Government always looks upon them with utmost care, and scrutinizes their every recommendation and suggestion, so that Government is in a position to know what is best for the institution, in the interest of the country—not in the interests of the Ministry or of any particular officer. So, when Dr. Ramji Singh mentioned this matter about the Estimates Committee which wants an indepth study for a fuller utilization of the assets etc. of the IIsT., certainly the Government is considering some of the recommendations—which have been made. But apart from the broad recommendations in the Estimate Committee's report, the other specific instances which Dr. Ramji Singh has mentioned, as I understand them, have not been mentioned by him out of the Estimates Committee's report. But his main criticism was confined to the various criticisms made by the Estimates Committee. Government is carefully considering these matters, and appropriate steps will be taken, and a report also will be placed before the Estimates Committee just as in the case of the Public Accounts Committee—about what action Government is taking in respect of these matters. Therefore, I request Dr. Ramji Singh most humbly that he should have patience to see what is being done so far as the report of the Estimates Committee is concerned.

He has mentioned many other cases of alleged gross irregularities but I should submit that the Half-an-Hour Discussion is raised on the basis of the question which was originally asked in this House and to which I had given some answers. In that answer I have stated that several complaints have been made against the Director of the Institute and the enquiry which was demanded by the hon. members of this House before the President, who is the Visitor of the Institute, was with regard to the conduct of the Director. I have got copies of the submission which was made. It was about the state of affairs of the IIT under the present Director, Dr. A Bhattacharjee and it demanded that the victimisation which had taken place under him should be looked into I have said that the Director is not all in all in this institution. I am not being legalistic nor do I want to mention about autonomy etc. at this stage. But I am simply stating that under the Act and the statute of the Institute —for that matter, all other Institutes— Director is one of the officers—principal officer no doubt—but his action is supervised by the Board of Governors, consisting of representatives of different States and also a large number of representatives of the Council of IIsT There is a Council of IIsT which looks after the affairs of IIsT as a whole Therefore, the specific points which have been mentioned by the hon members will be certainly sent to the Board of Governors for scrutiny and their statement will have to be obtained so that they might express their opinion. But some of the allegations which have been made against the Director by the hon. members of this House have already been considered by the Board and I do not know what else the Board will say.

Certain specific questions have been raised about financial irregularities. There is provision for audit not by any private auditor but by Government auditor, who scrutinises these matters. If there is really any financial irregularity, the Government auditor will certainly give his comment and on that appropriate action will be taken. Dr. Ramji Singh has said that he will make these papers available to me. If he kindly makes them available to me, certainly I will look into

[Dr Pratap Chandra Chunder]

the matter But I say once more that Government is keen that this prestigious institution along with other IIsT should be kept above board If there is any doubt about any affairs of these IIsT keeping in view the structure of the IIsT and the various bodies which exercise powers over IIsT, certainly Government will see to it that unnecessary criticism may not be levelled against these institutions I say with very great regret that some students of IIT Kanpur saw me sometime ago and pointed out that because of this publicity in the press criticising the IIT in this fashion their future is also at stake, because people will not have any faith in the degrees of the IIT I most humbly request hon members not to take to that line But if any real case is made out, there is the Board there is the Government Auditor or Accountant General, whatever he is called and it will be certainly scrutinised In addition, as Chairman of the Council of IITs, I may say that if Dr Ramji Singh can show me those cases specifically which cannot be satisfactorily explained by the IIT, then appropriate steps will be taken

DR RAMJI SINGH What about my suggestion to appoint a committee of say, 3 Members of Parliament?

DR PRATAP CHANDRA CHUNDER I respectfully submit that Members of Parliament have got greater responsibility towards the country in general and in the matter of investigation of the affairs of a single institution I should not think that Members of Parliament should spend their time

श्री कवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) सभापति जी, मै ने माननीय मंत्री महोदय क विचार सुने और मै उन से इस बात म सहमत हू कि किसी का भी यह विचार नही है कि आई0आई0 टी0 के बार म देश मे इम्प्रैशन खराब किया जाये। लेकिन साथ ही साथ आप का मालूम है कि 25, 30 एम0 पीज ने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को लिख कर भेजा है और उन से वह मिल भी है और उन्हो ने कुछ चार्जेज लगाये है।

आप ने सवाल के जवाब मे कई बार यूनिवर्सिटी के बारे म कहा है कि वह तो आटोनामस है, अभी भी आप ने कहा है कि उन का बोर्ड है, एक आदमी काम नही करता। ठीक है, वह बोर्ड है, लकिन जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या और यूनिवर्सिटीज है वहा भी वाइस-चासलर और एक्जीक्यूटिव काउसिल होती है लकिन वह एक्जीक्यूटिव काउसिल और बोर्ड डायरेक्टर क कहने के मुताबिक हो चलते है। यह प्राय हर जगह होता है, जो मिनिस्टर कहेग, कैबिनेट प्राय वही मानती है। स्मूथ वर्किग के लिये जरूरी भी शायद होगा, लेकिन इसलिय बोर्ड का रेफर करना, आप देखे, मै न देखा है, कि कुछ इर्रेगुलैरिटीज है, माल-प्रैक्टिसज है, शिकायत है और कुछ तो फाइनेन्शियल है कुछ एप्वाइटमेट के बारे मे है, कुछ मिसयूज आफ अथारिटीज और पर्सनल मिस-यूज क बारे में है।

फाइनेन्शियल इर्रेगुलैरिटीज का जहा तक सवाल है तो मै समझता हू कि आई0 आई0 टी0 आटोनामस भी हो, आप यह मानगे कि जो पैसा कसालिडेटिड फड आफ इडिया स दिया जाता है, पार्लियामट क जरिय स a University or any other authority is accountable to Parliament That, you agree and the PAC, the Estimates Committee and all that go into the matter IIT is also accountable to Parliament Inspite of the fact that it is an autonomous body it is accountable to Parliament I have had experience when I had been to Banaras Hindu University and all Central Universities There I came across the most alarming case in my life there was a deposit of about Rs crores in the bank in favour of Benaras Hindu University It is deposited in the Bank but the University does not know that the money is deposited in the Bank Have you come across such cases? This was pointed out by my Committee Inspite of repeated reminders, the Banaras Hindu University did not take any action or that Do you mean to say that this IIT so far as financial matters are concerned is not accountable to Parliament What did you do in that case? In one case

MR CHAIRMAN You must seek only clarification

SHRI KANWAR LAL GUPTA I am seeking only a clarification In one University, you have the audit second time, the Government audit second

time, the particular case mentioned in the complaint. So, even in this case, will you consider the proposal so far as financial irregularities like fraud or embezzlement are concerned and will you appoint some Government auditor again to go into the details and not to leave it to the Board of Directors?

18 hrs

I do not know to what extent the complaints are correct. There is a rumour that the Director is attached to you. Whether he is actually attached to you or not, I do not know. In your own interest, may I request you to refer all these cases to any person. regarding the appointment and all that, so that everything may be clear. These are my two questions. First, about the financial irregularities, will you appoint another audit, because the audit must have been over? But the same things about which a complaint has been made, will you refer to the audit as you have done in the case of one university? My second question is about the other matters which are only serious matters. If they are serious, will you appoint anybody, even the University Grants Commission or anybody in your Ministry? Will you appoint somebody to look into this? These are my two questions.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Hon. Member Shri Kanwarlal Gupta is a very experienced lawyer, and experienced parliamentarian as well. But I would respectfully say that his analogy of the Cabinet and the Prime Minister is not apt at all because the Ministers are appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister, whereas in the case of Board of Governors of IIsT, the Director has very little to say and as I said earlier, a large number of Members represent different States in that area and also on the Council of IIsT over which the Director has no control. However, I am not going into these technicalities. I fully agree with my hon. friend that no institutions which are being financed out of the funds of the government, i.e., out of public exchequer, will go scot free if there is any financial irregularity and the safeguard also is inbuilt in the statute. For instance, under Section 9(2) of the Institute of Technology Act, the provision is:

> "Visitor may appoint one or more persons to review the work and progress of any Institute and to hold inquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the Vsitor may direct."

The next sub-clause clearly points out that a Visitor can give direction to these IIsT for carrying out the directives. Therefore, ample power is there in the hands of the Government. But this is an extreme step. Unless a proper case is made out, this type of roving inquiries into these matters will create more confusion than it would solve. Therefore, I have submitted to Dr Ramji Singh, if he gives me some of these specific cases, certainly these will be looked into.

Shri Kanwarlal Gupta referred to two points. One is whether these financial irregularities can be referred to some Government auditor. If his cases can be specifically brought before me and *prima facie* Dr. Ramji Singh satisfies me then certainly I shall be prepared to refer this to Government auditor once more so that these matters might be checked up. As regards other matters, I have already made my submission.

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरिम मदर साहब, चूंकि ज्यादातर इल्जामात के बारे में कह दिया गया है, और वक्त नहीं रहा है, सिंहाजा मोहतरिम वजीर साहब ने श्री मनोहर लाल को जो जवाब दिया है, उस के मुताल्लिक मैं मालूम करना चाहता हूं कि आटोनोमस बाडी किस को कहते हैं । कोई भी आटोनोमस बाडी जिस मिनिस्ट्री में आती है, क्या वह मिनिस्ट्री उस की खराबियों के लिये जिम्मेदार नहीं है और पालिया-

[श्री रशीद मसूद]

मेंट को जवाबदेह नही है ? अगर वह जिम्मेदार और जवाबदेह है, तो मै यह नही समझता हू कि मिनिस्टर साहब सिर्फ यह कह कर मेम्बर, पार्लियामेंट की बेइज्जती कराते रहें कि आटोनोमस बाडी है, हम कुछ नही कर सकते है । मेरा ख्याल है कि

[شری رشید مسعود (سہارن پور) :

محترم صدر صاحب - چونکہ زیادہ تر الزامات کے بارے میں کہدیا گیا ہے اور وقت نہیں رہا ہے لہذا محترمہ وزیر صاحب نے جو جواب دیا ہے - اس کے متعلق میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آٹونومس باڈی کس کو کہتے ہیں - کوئی بھی آٹونومس باڈی جس منسٹری میں آتی ہے کیا وہ منسٹری اس کی خرابیوں کے لئے ذمے دار نہیں ہے - اور پارلیمنٹ کو جوابدہ نہیں ہے - اگر اور ذمے دار اور جوابدہ ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب صرف یہ کہہ کر ممبر آف پارلیمنٹ کی بے عزتی کراتے رہیں کہ آٹونومس باڈی ہے - ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں - میرا خیال ہے کہ ....]

सभापति महोदय . आप सिर्फ सवाल पूछें । डा० रामजी सिंह ने इस डिस्कशन को शुरू किया है । बाकी सदस्य सिर्फ सवाल पूछ सकते है । (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल (कानपुर) सभापति महोदय, यह मामला कानपुर का है, इस लिए मुझे भी सवाल पूछने का अवसर मिलना चाहिए ।

श्री रशीद मसूद : यह मामला इतना बड़ा है कि इस पर दो घटे का डिस्कशन होना चाहिए ।

[شری رشید مسعود : یہ معاملہ

اتنا بڑا ہے کہ اس پر دو گھنٹے کا

ڈسکشن ہونا چاہئے -]

PROF DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): We also have a few questions, Mr Chairman.

MR CHAIRMAN. Your names are not there

PROF DILIP CHAKRAVARTY: We, of course, submitted our names.

(Interruptions)

MR CHAIRMAN: You have given notices, but you have given notices after 11 O Clock That is why they were rejected So far as your name is concerned, your name is not there because in the ballot your name did not come

PROF DILIP CHAKRAVARTY: Because we would like to take an opportunity to put questions.

श्री रशीद मसूद क्या आटोनामस का मतलब यह है कि कोई भी मैम्बर आफ पार्लियामेंट उस के बारे मे कोई सवाल नही कर सकता है या उस के बारे मे कोई और चीज नही कर सकता है ? क्या आटोनामस बाडी का मतलब यह है कि वह जो चाहे करते रहे, चाहे जितनी इर्रेगुलेरिटी करते रहे, चाहे जितनी ला-कानूनियत करते रहे और कोई चैक नही हो सकता है ? वजीर साहब अगर यह समझते है कि ये दोनो बाते है, तो ऐसा कहे, फिर यकीनन मुश्तकबल में कोई एम पी सवाल नही करेगा और अगर ये बाते नही है तो वजीर साहब आटोनामस का बहाना कर के हमारे प्रश्नो का जवाब देने से मना न करें ।

[شری رشید مسعود : کیا آٹونومس

کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ممبر

آف پارلیمنٹ اس کے بارے میں کوئی

سوال نہیں کر سکتا ہے - یا اس

کے بارے میں کوئی اور کیس

نہیں کر سکتا ہے - کیا آٹونومس باڈی
کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتے
رہیں - چاہے کتنی اوریگولیریٹی کرتے
رہیں - چاہے کتنی لا قانونیت کرتے
رہیں - اور کوئی چیک نہیں کرتا
ہے - وزیر صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ دونوں باتیں ہیں تو ایسا کہیں
پھر یقیناً مستقبل میں کوئی ایم- پی-
سوال نہیں کریگا - اور اگر یہ باتیں
نہیں تھیں تو وزیر صاحب آٹونومس
کا بہانا کرکے ہمارے سوالوں کا جواب
دینے سے منع نہ کریں -]

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): On a point of order. The House was scheduled to sit only up to 6 O'Clock. The consent of the House should have been secured for extension. If, without securing consent, the House continues for six minutes, certainly, though our names are not there, we can secure the consent of the House and put questions. I move that the House continue up to 7 O'Clock and the other Members also be allowed to put questions.

MR. CHAIRMAN: You have raised a point of order. It is correct that I should have asked the pleasure of the House. I thought the questions would be over within five minutes, but it has been prolonged.

Is it the pleasure of the House to sit for another ten minutes?

HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Even if it is extended by one hour, you are not going to be called because your name has not come in the ballot. It is not going to benefit you.

The House will be extended by ten minutes.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: There is no question of showing any disrespect to the hon. Members of this House. They are putting questions. In fact, with regard to this IIT, Kanpur, several questions have already been put, and we are discussing all these matters in this House. Similarly, in the other House also questions are being put. If, on the plea of autonomy, there is no accountability, we would not have answered the questions at all. The fact that we are answering questions shows that we are having respect for the Members. I am also a Member of the House and some day I may be on the other side and would like to put some questions. So, how can I show disrespect to the Members?

Parliament has passed certain Acts and statutes on the basis of which certain powers have been delegated to these institutions, and within the framework of the powers which have been delegated to them, they can take decisions. For instance, dismissal of an employee. It is a case of the domestic tribunal and if the rules have been duly complied with, even a court of law will not interfere.

Then again, there is also powers with the court of law to see whether the rules are complied with or not.

Autonomy is enjoyed by these institutions to the extent spelt out by the Act of Parliament. Therefore, when we speak of autonomy, it does not mean that there is no accountability. I have read out the portion from the very Act to show that the Visitor, on Government advising him, can take action in this matter. So, the apprehension of the hon. Member is not correct.

सभापति महोदय : श्री ब्रज भूषण तिवारी, आप सिर्फ सवाल पूछिए ।

एक माननीय सदस्य : हर आदमी को सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, यह मामला हमारे कानपुर का है । हम यह मानते हैं कि आप के रूल्स एंड रगुलेशंस के मुताबिक हमारा नाम बैलट में नहीं आया लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे, यह हमारे क्षेत्र का मामला है, शुरू में मैं ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया है और तीन बार शिक्षा मंत्री से मिला हूं, तीन बार राष्ट्रपति से मिला हूं, वहां की तमाम अनियमितताओं के बारे में, डायरेक्टर की तानाशाही के बारे में, डायरेक्टर के श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी से संबंधों के बारे में,–यह सारी चीजें लिखी गई हैं और पेपर्स में छपी हैं लेकिन इस के बावजूद बैलट में चूंकि मेरा नाम नहीं आया इसलिये मुझ बोलने का मौका नहीं मिला, हम आप से डिमाण्ड करत हैं कि इस पर दो घंट की चर्चा होनी चाहिय जैसा कि स्पीकर साहब ने 2 तारीख को आश्वासन दिया था । यहां पर डायरेक्टर बैठ हुए हैं . . . .

सभापति महोदय : हम आप के जजबात की कद्र करते हैं, यह आप के क्षेत्र का मामला है लेकिन मैं क्या करूं ? मैं मजबूर हूं । यह आप की बदकिस्मती है कि बैलट मे आप का नाम नहीं आया । आप 2 घंट की चर्चा के लिए स्पीकर साहब से डिमान्ड कर सकते हैं ।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: We all endorse the views of my friend, Mr. Manoharlal. Let there be a two hour discussion. We all want to participate in the discussion.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Manohar Lal, your feelings will be conveyed to the Speaker.

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, आई आई टी, कानपुर में अनियमितताओं और मनमानी नियुक्तियों तथा प्रदोन्नति के सम्बन्ध में तमाम बातें कही गई हैं । डा० रामजी सिंह ने बहुत से तथ्य आप के सामने रखे हैं । इस के पहले भी प्रधान मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री को लिखित रूप में कई सदस्यों ने दिया है, इस सदन में भी नियम 377 के अन्तर्गत मामले को उठाया गया है और सवाल भी हुए हैं लेकिन इस के बावजूद शिक्षा मंत्री अपनी आंखें बन्द किए हुए हैं । इतना सब होने के बावजूद उन को कोई प्राइमा-फेसी केस नजर नहीं आता । मैं उनके उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा, पिछली बार जिस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है, श्रीमती पार्वती कृष्णन का प्रश्न था, उस में उन्होंने लिखा था . . . .

"There was a complaint that one Principal of Compus, Shri J. S. Mittu was dismissed. He was dismissed after following all the details of procedure. Then this Gentlemen went to the High Court and the High Court dismissed his application. Then political pressure was brought to bear in this Institute."

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: On a point of order. The hon. member has placed this matter before the hon. Speaker on a question of privilege for misleading the House. So it is under consideration of the hon. Speaker. A question of privilege has been raised over this matter. When the matter is referred to the Speaker, I submit that this should be placed before the hon. Speaker.

श्री ब्रज भूषण तिवारी : अगर प्रिविलेज का मामला उठाया गया तो उस का जवाब आयेगा लेकिन यह जो आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है, इस प्रश्न का जो उत्तर था वह बिल्कुल झूठ, गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं है । श्री जे एन मट्टू ने स्वयं मुझे पत्र लिख कर कहा है कि मैं ने हाईकोर्ट में कोई मुकदमा या किसी प्रकार का केस दायर नहीं किया इसलिये खारिज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि 3 दिसम्बर, 1977 को "ब्लिट्ज" में छपा था कि आई आई टी कानपुर में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्यायें सब से अधिक हैं । इसके अलावा आज भी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल चल रही है । तमाम प्रकार के धरने हुए हैं । अध्यापकों में असन्तोष है, विद्यार्थियों में असंतोष है । तमाम लोगों ने शिकायतें लिख कर भेजी हैं । इतना ही नहीं, जो जे ई ई के एग्जामिनेशन होते हैं उन में भी व्यापक पैमाने पर धांधली की गई है । इस धांधली के बारे में भी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्राइमा-फेसी केस नहीं बनता इसीलिए अगली कार्यवाही नहीं की गई ।

इसी सम्बन्ध में मैं ए के दर कमेटी की रेकमेंडेशन्स से दो चार लाइनें सुनाना चाहता हूं :

"As suggested by you, I have examined the papers regarding the joint entrance examination conducted by the Social Committee and my observations are as follows:

"There appears to be overwriting in respect of Code Nos. NW 64, MX 41 and F2 42.

In respect of these candidates, the original works have been altered. No initials had been put against the

above-mentioned instances of overwritings There is no recorded evidence of any policy decision having been made in this connection, by the Committee. No uniform criteria appear to have been followed in making the alterations.

In view of the above facts, I am of the opinion that a *prima facie* case for inquiry exists against the individual who has made the alterations."

This is dated April 10, 1976.

इस के बाद इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही हुई ।

फिर अनुसूचित जातियों के बारे मे एस्टीमेट्स कमेटी ने भी लिखा है कि यहा पर एक श्री आर० आर० वर्मा थे, जिन का प्रोमोशन हुआ था एज ए सुपरिन्टेन्डेन्ट परन्तु जो वतमान डायरेक्टर है उन्हो ने उन को चार्ज नही लेने दिया । उस संस्था के चेयरमैन मि० थापर है और हम तो यह दखते है कि जितने भी आई० आई० टीज० देश मे है, उन के चेयरमन बडे उद्योगपतियो और कारखानेदारों को ही बनाया जाता है जो अपने धन्धो में व्यस्त रहते है और केवल एक रबड-स्टैम्प की तरह काम करते हैं । वह डायरेक्टर के कब्जे में रहते है । मि० वर्मा जो थे, उन को चार्ज नही दिया गया और गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो ला मिनिस्ट्री है, उस ने अपनी रिपोर्ट मे साफ यह राय दी है कि इन के साथ ज्यादती हो रही है मगर चेयरमैन मि० थापर जो है, जिन को हमारे श्री मनोहर लाल पत्र लिखते हैं, वे उनको धमकी देते है । यह जनवरी 12, 1979 की चिट्ठी है, जिस मे से मे पढ कर आप को सुनाता हूं:

'I am also of the opinion that if the question is not allowed to be closed, it is likely to land Shri Varma into difficulty which I would not like to happen if I can help it."

इस प्रकार की धाधले बाजी होती है और इस प्रकार की धमकी वहां के कर्मचारियों को दी जाती है जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, जिस के बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहा के जो रजिस्ट्रार हैं, उन को बिना किसी औचित्य के और बिना किसी कारण के ससपैंड कर दिया गया । 19 जनवरी, 1979 को गवर्निग बाडी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ससपेंशन की कोई चर्चा नहीं हुई । 23 जनवरी को श्री के० पी० सिंह ने, जो गवर्निंग बाडी के सदस्य है, मि० थापर को लिखा कि रजिस्ट्रार गिरराज किशोर के बारे मे क्या कार्यवाही हो रही है । इस के बावजूद भी 19 जनवरी को वहा जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस की कोई चर्चा गवर्निग बाडी में नही हुई मगर बैक डेट मे चेयरमैन से ससपेशन आर्डर पर दस्तखत करा दिये गये । 19 जनवरी के लैटर में यह बात बताई गई है । इसी प्रकार से और भी बातें है । एक नही बल्कि बहुत सी ऐसी बातें हैं । जो रजिस्ट्रार, फाइनेन्स है, इन की नियुक्ति कब हुई । गवर्निग बाडी की 45 वी मीटिंग म यह हुई थी । इस सम्बन्ध में मैं दो लाइन आप को पढ कर सुनाना चाहता हू । इस मे साफ तौर पर यह कहा गया है :

"Assessment scheme for promotions to high posts "

यह बात उस मे तय नही हुई थी कि हाई पोस्टो के लिए यह है बल्कि जो और पोस्टे है उन की नियुक्ति के बारे म है मगर इस को वायलेट कर के मि० एस० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई क्योंकि सारे घोटाले, सारी टेक्नीकल एजूकेशन जो ग्रान्ट है उस का 70 फीसदी पैसा इन बडे हाथियो को दिया जाता है, सात सात करोड, छ छ करोड रुपये की ग्रान्ट उन को मिलती है । इसलिये फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट मे ऐसा आदमी होना चाहिये, ऐसा रजिस्ट्रार होना चाहिये जो इन की मनमानी को माने । इस प्रकार की नियक्ति कर के ये अपने ही आदमी को रखते हैं । तो मै एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि तमाम अखबारो मे सारी बातें कही गई है, ग्लेरिंग इन्सटान्सेज इर्रेगलेरिटीज की है और फाइनेन्शियल करप्शन की बाते भी कही गई है और जाच कराने का प्राविजन भी है और अभी हाल मे वहा के डाइरेक्टर ने स्वय वहां के स्थानीय अखबारो मे यह बयान दिया था कि मै जाच कराने के लिए तैयार हू और इस में ओटोनामी की कोई अडचन नही बनती है परन्तु पता नही सरकार क्यो हिचकिचा रही है । यह एक विचित्र स्थिति है कि वहां का डायरेक्टर बयान देता है कि जांच कराओ और हमारे शिक्षा मंत्री की आखो पर पट्टी बंधी है । कि कोई प्राइमाफेसी केस नही बनता है, मै स्पष्ट तौर पर उत्तर चाहूंगा कि जब इस प्रकार के गंभीर आरोप है, एस्टीमेट कमेटी में आरोप है और तमाम संसद सदस्यो ने लिखित शिकायतें की हैं, विश्वविद्यालय का पूरा वातावरण अशांत और क्षुब्ध है, डायरेक्टर के कहने के बावजूद भी ऐसी कौन सी बात हैं कौन से कारण है कि आप जांच कराने में हिचकिचा रहे है ?

दूसरी बात मै यह जानना चाहता हूं कि आई० आई० टी० की गवर्निंग बाडी के चेयरमैन पद पर थापर और सिंघानिया जैसे बडे बड़े पूंजीपतियों के बदले में क्या आप अच्छे किस्म के लोगो को चेयरमैन पद पर नियुक्त करने पर विचार करेंगे जो कि अपना अधिक समय वहां दे सकें और शिक्षा की तरक्की में भी योगदान कर सकें ।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The hon. Member has mentioned three matters which are now the subject-matter of the privilege matter

[Dr. Pratap Chandra Chunder]

which has been mentioned before the hon. Speaker. So, I do not want to comment on these. Sufficient explanation will be given to the hon. Speaker, and let him decide who is right and who is wrong. So, I am not making any comment on these.

About suspension of the Registrar, I may say, it is not only suspension but actual steps have been taken to initiate disciplinary proceedings according to law; a charge sheet has been served on him. There are several heads of charges. There are four articles of charges Under them, altogether 26 items of dereliction of duty, omission and commission have been mentioned. A retired judge, Justice R. K. Baveja, a retired District and Sessions Judge, Punjab Judicial Service, who was also in the Commission of Inquiry which inquired into the liquor death by using spurious liquor in Delhi in 1972, and who was again in the Commission of Inquiry for inquiring into the lathi-charge of political prisoners during Emergency on 2nd October 1975, has been appointed to look into this matter. This matter is now before the Inquiry Committee and, as I have said, that is perfectly within the domestic jurisdiction of this institution. Government is not going to interfere in this matter.

As regards various other matters which the hon. Member has referred to, I would say, the charge is not only against this institution. Shri Manohar Lal was saying that it related to his constituency. I knew only yesterday that he has also levelled charges against the IIT, Bombay. There may be charges against all the IITs. Therefore, this Government will scrutinise all these charges. Merely because certain charges have been signed by a number of MPs, it will not mean that the charges are substantiated. This is what has been stated in the letter addressed to Shri N. Sanjiva Reddy, President of India:

> "The present Director is a man who is devoid of ideals and values. He got this assignment as a reward for his allegiance to the former rulers of the country. He is a great admirer of Sanjay Gandhi whom he cultivated with assiduous zeal...."

> "The Director follows the British policy of divide and rule to keep himself in power."

This Director offered to resign last year. But a number of professors came to me and said that this should not be done. I called the Director and said that that would bring a bad name to the institution if he did not face the situation

As regards the appointment of Chairman, it is not a fact that every time we appoint some industrialist. For instance, in Delhi IIT, we have appointed Air Marshal Arjun Singh, who is a member of the Minorities Commission In Bombay IIT, there is a very well known scientist. But wherever we feel that particular persons will contribute to the general development of this institution, certainly we should consider them.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday.

18.25 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 30, 1979/Vaisakha 10, 1901 (Saka).

MGIPND—M—799LS—